

Review Of Research



जैसा समाज वैसी पुलिस

सार : 191— मथुरा बलात्कार कांड,
1980— भागलपुर ऑखफोडवा कांड,
2002— गुजरात दंगों में संदिग्ध भूमिका,
2011— दिल्ली के रामलीला मैदान में मध्यरात्रि को 50 हजार से ज्यादा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठी-चार्ज,

कुमार आशीष

भा. पु. से. (2012 बैच) स्थायक पुलिस अधीक्षक, प
BegusaraBallia, Begusaraj, Bihar.



1. प्रस्तावना :

2013 पाँच वर्षीय गुडिया के सामूहिक बलात्कार मामले को रफा-दफा करने के लिए पुलिस द्वारा 2000 रुपये की रिश्वत की पेशकश और प्रदर्शनकारी छात्राओं पर दिल्ली पुलिस का बल-प्रयोग

सन 2013 बिहार के जमुई जिले में पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मिर्च पाउडर और पेट्रोल डाल कर हुई प्रताड़ना के उपरान्त मृत्यु मुंबई, गुजरात, दिल्ली और भारत के कई शहरों में हुए एवं नित्य हो रहे फर्जी एनकाउंटर्स की लम्बी फेहरिस्त....

और भी ऐसे अनगिनत मामले पुलिस कि ज्यादाती से जुड़े हुए हैं। और भी ऐसी कोई हृदय विदारक घटना है तो जोर-शोर से समाज पुलिस महकमे को अपराधी को साबित करने में लग जाता है। परन्तु इस बीच हम यह भूल जाते हैं कि पुलिस भी चूँकि समाज से ही निकलती है इसीलिये यह अवश्यंभावी है कि पुलिस का चरित्र भी वैसा ही होगा जैसा कि हमारे समाज का है।

चूँकि यह समाज एक आदर्श समाज नहीं है इसलिए पुलिस भी आदर्शवादी नहीं हो सकती। समाज की कुरीतियाँ यथा जातिवाद, संप्रदायवाद, पितृसत्तात्मक एवं सामंतवादी मानसिकता, भ्रष्टाचार इत्यादि सामाजिक बुराइयों अगर पुलिस में भी दृष्टिगोचर हो तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वस्तुतः यह परस्पर सहजीविता के नियमों कि आवश्यकता को इंगित करता है जहाँ संवेदी पुलिस एक सशक्त समाज का होना अपरिहार्य है।

भारतीय पुलिस व्यवस्था सन् 1861 के सामंतवादी पुलिस संहिता से संचालित होती है जो आज भी करीब 150 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी प्रचलन में है। इस संहिता का निर्माण तात्कालिक जरूरतों के मुताबिक एक सुसुप्त मानसिकता वाले गुलाम देश को गुलाम बनाए रखे जाने के लिए हुआ था। अस्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह संहिता उत्तरदायित्व, समरूप एवम् पारदर्शिता के मानकों पर खरी नहीं उतरती।

पुनश्च: पुलिस और समाज का सम्बन्ध मैत्रीभाव, बंधुत्व एवम् आपसी सदभाव की एक कड़ी माना जाता है जो पुलिस और समाज को सामान्य उद्देश्यों जैसे शान्ति और कानून व्यवस्था, सामाजिक अधिकारों एवम् नागरिक स्वतंत्रताओं को चलायमान रखने के लिए एक सूत्र में बांधती है। अतः सामाजिक जीवन का प्रतिबिम्बन पुलिस व्यवस्था में स्पष्टतया परिलक्षित होता है। यह प्रतिबिम्बन विकसित समाजों तथा अल्पविकसित समाजों में देखा जा सकता है जहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली सर्वथा भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश, अमरीकी और फ्रेंच पुलिस मनोवैज्ञानिक दबाव तकनीक के द्वारा अपराधियों से अपराध कुबुल करवाते हैं जबकि एशियाई, मध्य-अफ्रीकी एवम् कैरेबियाई समाजों में मार-पीट (थर्ट डिग्री) कि सहायता आज भी ली जाती है। पश्चिमी समाजों में पुलिस अपने नागरिकों के साथ काफी सभ्य तरीके से पेश आती है जबकि हमारे यहाँ पुलिस में भर्ती होना ही गुंडागर्दी की शुरुआत मानी जाती है, सभ्य तरीका तो भूल ही जाईये। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे समाज में एक आम आदमी के जेहन में पुलिस की रौबदार छवि ही बसती है और उस दबंग व्यवहार की वजह से ही पुलिस अपना कार्य करने में सक्षम हो इसका प्रदर्शन हम सबने गाहे-बगाहे देश के विभिन्न शहरों में चौक-चौराहों पर देखा ही है।

भारत में वर्तमान समय में पुलिस पर भ्रष्टाचार एवम् सम्बेदनहीनता के महती आरोप लग रहे हैं तथा कई मामलों में ये आरोप साबित भी हो चुके हैं। परन्तु वैचारणीय प्रश्न यह है कि हम खुद एक समाज के रूप में कितने ईमानदार एवम् संवेदनशील हैं? जरा सोचिये: जंतर-मंतर, रामलीला मैदान या इंडिया गेट की अनशन सभाओं में छुट्टी के दिनों में थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए भारी संख्या में हमलोग जाते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जोर-शोर से नारे लगाते हैं, परन्तु ऑफिस की सरकारी वस्तुओं का निजी प्रयोग करने में तानिक भी संकोच नहीं करते, सरकार को वेट टैक्स ना देना पड़े इसके लिए दुकानदार से पक्का बिल नहीं मांगते, इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह के तीन-तेरह करते, ट्रेन के सफर में एक-एक सीट के लिए 500-1000 की रिश्वत टीटी को देने से नहीं हिचकते, मंदिर-मस्जिद के नाम पर एकत्रित चंद से अपना घर सजाने से नहीं चुकते, और स्वनिहित स्वार्थ के लिए किसी को भी जरिया बनाने से गुरेज नहीं करते—और इन सबके बाद खुद अमावस के चोंद के मानिंद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहनेवाले हम सामाजिक लोग, पुलिस से दूज के चोंद कि भांति निष्कलंक होने की अपेक्षा रखते हैं।

और आइए, अब बात करते हैं सम्बेदनशीलता की — लाखों लोग दिल्ली गैंग-रेप के बाद धरने-प्रदर्शनों में शामिल हुए और जी भर के पुलिस के नाम का मर्सिया पढ़ा गया, परन्तु क्या ये किसी आम नागरिक का फर्ज नहीं था कि उस क्षत-विक्षत निर्भया एवम् उसके मृतप्राय साथी घंटे के दौरान इस देश का कोई भी “संवेदनशील नागरिक” उस व्यस्त दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से नहीं गुजरा था? कहाँ गए हमारे सामाजिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व? याद रखिए, एक सभ्य समाज में पुलिस का व्यवहार अलग होता है और एक असभ्य समाज में एकदम अलग। आप जैसे समाज में रहते हैं, पुलिस भी उसी समाज का आइना होती है।

हालाँकि, बदलते हुए समाज का पुलिस कि कार्य प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है जिसके बेहतर उदाहरणों में शीला बरसे बनाम भारत सरकार (1994) केस का उल्लेख किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप महिला सुरक्षा जॉच एवम् पूछताछ में किसी महिला पुलिस कि उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी। दूसरा मामला डी के बासु का था जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए 11 दिशा-निर्देश जारी किए। ये परिवर्तन समाज के बदलते स्वरूप और जरूरतों का पुलिस के कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का परिचायक है। बिहार में भी पुलिस महकमें द्वारा अभियुक्तों को किसी भी तरह की शारीरिक यंत्रणा देने पर सख्ती से पाबन्दी लगाई गयी है जिसका सुपरिणाम अब दृष्टिगोचर होने लगा है।

सम्प्रति, पुलिस को समाजोन्मुखी बनाने के महती प्रयास चल रहे हैं। वर्तमान समय कि जरूरतों के हिसाब से पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी, संगणक एवम् दूरसंचार के नवीनतम साधनों का समुचित प्रयोग कर रही है। समुदाय पुलिसिंग तथा समस्या-उन्मुखी पुलिसिंग समाज कि बढ़ती आवश्यकताओं का ही फलित रूप है। सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्स एप्प एवं ट्विटर आदि पुलिस में समाज की बढ़ती हिस्सेदारी का ही परिचायक है। लेखक द्वारा बिहार में मोतिहारी (ट्रेनिंग के दौरान) एवं दरभंगा जिले में फेसबुक पर जिला पुलिस का पेज खोला गया जिसमें समाज की भागीदारी का आह्वान किया गया था। बिहार में ये प्रयोग नवीनतम है और दोनों जिलों की जनता ने इनका तहेदिल से स्वागत किया। इस पेज के माध्यम से पुलिस द्वारा आम जनता के वेलफेयर से जुड़े मामलों पर संज्ञान लिया जाता है।

और त्वरित कारवाई की जाती है। इसमें ज्यादातर मामले किसी खास एरिया में अवैध शराबबंदी , ट्रैफिक समस्या, जमाखोरी –कालाबाजारी , छेड़खानी , स्थानीय लफंगों के विरुद्ध शिकायतें आदि होती है जिसमें कॉलन पब्लिक प्रभावित होती है। इस पेज के माध्यम से लोगों में ट्रेफिक सेंस विकसित करने में सहायता मिलेगी और साथ ही उनके की सहयोग से पुलिस समाज की कॉमन बुराईयों से लड़ने में सक्षम हो सकेगी क्योंकि बिना पब्लिक के सहयोग के समाज की पुलिसिंग अधूरी ही रहेगी। सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस- प्रशासन का आम जनता के नाम आवश्यक सन्देश भी त्वरित गति से पहुँच सकेगा एवं उस सन्देश पर जन –मानस के विचार भी हमें अत्यंत अल्प समय में उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही ये व्यवस्था पुलिस महकमे को पारदर्शी बनाने में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्षत-

पुलिस को और भी ज्यादा पारदर्शी, उत्तरदायी एवम् मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए समाज को भी स्वतःस्फूर्त सुधार की प्रक्रिया से गुजरात होगा। जो-जो सुधार समाज पुलिस में देखना चाहता है, वो सारे सुधार समाज को खुद आत्मसात करने होंगे और तब पुलिस एवम् समाज का सामंजस्य प्रगति के नए आयाम खोलेगा जिसकी बानगी इन चंद पंक्तियों में इस प्रकार कि जा सकती है:

“ मर्यादा में रहोगे तो नदी कहाओगे,
निज नाम करोगे दूसरों के काम आओगे
सीमा में बहती है नदी जब तक सभी गुणगान करते हैं,
सीमाएँ तोड़ देती है जब नदी, उसे बाढ़ कहते हैं.
अब निश्चय तुम्हारा है बनी नदी या बाढ़ बन जाओ
करो पर हित या त्रास बन जाओ।”